30 फूड टेस्टिंग किट खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करेगा खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआइ देशभर में अपने राज्य स्तरीय फील्ड अधिकारियों के लिए। नई किट ज्यादा तेज, बेहतर और पहले से सस्ती होंगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 2 जनवरी 2020

हिमाचल प्रदेश

सुरक्षा के लिए सतर्क रहें

शांति के लिए पहचान बनाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश की वादियां अगर अशांत हो रही हैं तो यह समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश में चोरी, लूटपाट, डकैती, दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि रिश्तों की मर्यादा को भी तार-तार करने से परहेज नहीं किया जा रहा। हैरत है कि अवैध संबंधों में बाधक बने बेटे की हत्या का आरोप मां पर लगा है। एक सप्ताह में ही इस तरह की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दोनों मामलों की पुलिस जांच कर रही है। पड़ोसी राज्यों के साथ सटे क्षेत्रों और राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में अपराध दर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कई बार तो पड़ोसी राज्यों के लोग प्रदेश की सीमा के भीतर अपराध कर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला कांगड़ा जिला के फतेहपुर के निकट खटियाड़ का है। यहां पर एक वृद्ध दुकानदारों को गाड़ी से इसलिए रौंद दिया, क्योंकि उसने मछली खिलाने के बाद पैसे की मांग की थी। पंजाब के हाजीपुर क्षेत्र के कुछ युवा गाड़ी से खटियाड़ आए थे। यहां पर उन्होंने एक दुकान पर मछली खाई। जब दुकानदार ने उनसे पैसे मांगे तो वे उससे उलझ पड़े और अपने वाहन में सवार हो गए। दुकानदार भी उनकी गाड़ी के पीछे भागा तो उन युवकों ने गाड़ी को पीछे कर उसे रौंद दिया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। इस तरह की वारदातें बढ़ने से लोगों में भय होना लाजिमी है। आज समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अधिकांश लोगों की सोच का स्तर गिर रहा है। आज ज्यादतर लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अंधे हो गए हैं। स्वार्थ ने उनकी सोच पर पहरा लगा दिया है। वे समाज के हित की बात न कर सिर्फ अपने ही हित की चिंता में लगे रहते हैं। इसी गलाकाट दौड़ में आगे निकल जाने के लिए हर अच्छे-बुरे साधनों का बेहिचक इस्तेमाल कर रहे हैं। यही मानसिकता समाज में बढ़ते अपराध की एक वजह बन रही है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह वे किसी का भला नहीं कर रहे हैं।

समाज में अपराध तभी बढ़ता है, जब लोग सतर्क नहीं होते। अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए सबको एक होना होगा

इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही सही है समाज में अपराध तभी बढ़ता है जब समाज में सतर्कता का अभाव होता है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी ढील रहती है कि सीमांत क्षेत्रों में इस तरह की वारदातें होने के बावजूद वहां पर पुलिस बल अधिक सतर्क क्यों नहीं किया जाता। सीमांत क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की भी धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। नशे के कारण यहां मौतें भी हो रही हैं इसके बावजूद नशे के सौदागर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन क्षेत्रों में महिलाएं भी नशे के कारोबार में संलिप्त पाई जा रही हैं। कई बार पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इस काले कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि लोग सतर्क रहे हैं, यदि कोई संदिग्ध गतिविधि देखें तो उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

जम्मू-कश्मीर

स्वच्छता में पिछड़ता जम्मू

स्मार्ट सिटी की तरफ कदम बढ़ा रही जम्मू-कश्मीर की दोनों राजधानियां श्रीनगर एवं जम्मू बुरी तरह से प्रदूषण की चपेट में हैं। इन शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचना चिंता का विषय है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन प्रदूषण रोकने के लिए प्लास्टिक वेस्ट को ठिकाने लगाने में फिसड्डी साबित हुआ है। शहरी क्षेत्रों के स्वच्छता सर्वेक्षण की दो तिमाही के नतीजों पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में जम्मू शहर कुल 733 में से 318वें नंबर पर आया है। जबकि श्रीनगर शहर 45वें स्थान पर रहा। विडंबना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण की कार्ययोजना तक नहीं बनाई। गत वर्ष मई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जम्मू-कश्मीर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी किया। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे श्रीनगर एवं जम्मू गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं। गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जम्मू शहर में तवी नदी में 14 बड़े नाले गिर रहे हैं। विडंबना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना वर्ष 2008 में शुरू तो हुई, लेकिन पुराने शहर को सीवरेज से नहीं जोड़ा गया है। तवी नदी में गिरने वाले गंदे नालों की निकासी के लिए अलग से पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। जिससे रोजाना जम्मू में चार सौ मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है। जिसमें प्लास्टिक वेस्ट सबसे घातक है। इस वेस्ट को ठिकाने

प्रतीकात्मक

लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका अभी तक नहीं अपनाया गया है। इतना ही नहीं श्रीनगर और जम्मू शहर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई योजना नहीं है। जहां तक ध्वनि प्रदूषण का सवाल है। अंबफला चौक पर यह 79.31 डेसिबल है, गुम्मट चौक पर 81.06 डेसिबल तक पहुंच गया है। जम्मू मेडिकल कॉलेज चौक पर भी यह ध्वनि प्रदूषण 75.88 डेसिबल है, जो खतरे से ऊपर है। अगर उप राज्यपाल प्रशासन जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने में वाकई गंभीर है तो सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक कचरा निस्तारण जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीरता दिखानी होगी। अन्यथा जम्मू स्वच्छता की दौड़ में हर बार पिछड़ता रहेगा।

प्रदूषण की बढ़ती समस्या से हम सब वाकिफ हैं। हमारे सामने वायु प्रदूषण के रूप में एक बड़ी चुनौती खड़ी है। वायु प्रदूषण मुद्दे को अक्सर केवल बड़े महानगरों के लिए एक चिंता का विषय माना जाता रहा है, लेकिन अब छोटे नगर और शहर भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। 102 शहरों में निर्धारित वायु की गुणवत्ता कम पाई गई है। लैंसेट प्लैनेट हेल्थ 2019 में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार 2017 के दौरान भारत में क्रमशः 6 लाख और 4 लाख 80 हजार लोगों की मौत का कारण बाहरी और घरेलू वायु प्रदूषण को माना गया। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका तत्काल कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसे कम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। यही स्थिति आज जल के साथ भी है। हमारा जीवन जल पर निर्भर है, लेकिन हमने खुद ही इसे प्रदूषित कर दिया है। आज कई बीमारियां प्रदूषित जल की देन हैं। प्रदूषित जल के पीने से मरने वालों की संख्या लाखों में है।

इसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण से इंसान में चिड़चिड़ापन, तनाव, बेवजह चिंता रहना आदि की शिकायत होती हैं। लोगों को भी चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों, क्योंकि अगर इसमें विलंब हुआ तो आने वाली पीढ़ियां हमें कतई माफ नहीं करेंगी। राज्यपाल को चाहिए कि मामले को गंभीरता से लें।

पंजाब

खजाने की चिंता

बड़े उद्योगों के बजाय छोटे उद्योगों को ही बिजली पर सब्सिडी देने की सिफारिश कर पंजाब का वित्त विभाग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे सूबे के खजाने को बचाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाने जा रहा है। ऐसे कदमों की ही इस समय जरूरत भी है, क्योंकि यह तो मानना पड़ेगा कि राज्य की खस्ता माली हालत के लिए मुफ्त में सौगातें बांटने या सब्सिडी देने का चलन भी जिम्मेदार है। सच तो यह है कि इस चलन का एक बड़ा कारण सियासी लाभ उठाना है। एक बार सरकार ने किसानों को मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की तो उसके बाद आने वाली सरकारें इसे खत्म करने का जोखिम उठाने का साहस नहीं कर सकीं। उल्टा यह देखा जाता रहा है कि अब किस वर्ग को लुभाया जाए। बड़े उद्योगों को बिजली पर सब्सिडी देने का एलान भी ऐसी ही कवायद मानी जा सकती है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ तो सरकार पर दो लाख करोड़ रुपये के करीब का कर्ज चढ़ चुका है, उसके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह से सौगातें बांटी जा रही

प्रतीकात्मक

हैं। किसानों को ही खेतों में ट्यूबवेल के लिए मुफ्त में बिजली देने से सरकार पर छह हजार साठ करोड़ रुपये का भारी भरकम बोझ पड़ता आ रहा है। इसलिए लगातार विकराल होते जा रहे आर्थिक संकट के मद्देनजर वित्त विभाग की यह सिफारिश महत्वपूर्ण है कि बिजली पर सब्सिडी केवल छोटे उद्योगों को ही दी जाए, बड़ों को नहीं। वैसे तो पहले ही यह होना चाहिए था, लेकिन अब देर से ही सही, सरकार को इसमें सुधार कर लेना चाहिए ताकि अनुमानित एक हजार करोड़ रुपये सालाना की बचत हो सके। बचत के इस तरह के उपाय करके ही आर्थिक संकट को कम किया जा सकता है। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मुफ्त में जब कोई सुविधा मिलती है तो उपभोक्ता कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग भी करता ही है, इसलिए मुफ्त के बजाय सब्सिडी पर सुविधा प्रदान करना फिर भी ठीक है, लेकिन वह भी तर्कसंगत होना चाहिए। उद्योगों को बिजली के अलावा और अन्य क्षेत्रों एवं मदों पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इन दिनों लगातार विकराल होते जा रहे आर्थिक संकट के मद्देनजर पंजाब के वित्त विभाग की यह सिफारिश काफी महत्वपूर्ण है कि बिजली पर सब्सिडी केवल छोटे उद्योगों को ही दी जाए, बड़ों को नहीं

बंगाल

तृणमूल की यात्रा

तृणमूल कांग्रेस ने अपना 22वां स्थापना दिवस बुधवार को नागरिक दिवस के रूप में मनाया। तृणमूल की दो दशकों से अधिक लंबी इस यात्रा ने कई उतार-चढ़ाव देखे। इस बीच बंग भूमि की सियासत को भी नए-नए अनुभवों से गुजरना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना से पहले 1997 तक कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रही ममता बनर्जी को वामपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी थी। इसके पहले वह सांसद और केंद्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी थीं, लेकिन उनके आक्रामक तेवर को तृणमूल बनने के बाद ही विस्तार मिला। वामपंथ के लाल किले को उखाड़ फेंकने के लिए ममता ने संकल्प लिया और कामयाब भी हुईं। पर इस यात्रा में उन्हें कभी कांग्रेस के साथ तो कभी भाजपा के साथ समझौता करना पड़ा।

ममता ने अवसर की नब्ज समझने में कभी चूक नहीं की। जब जिसे चाहा झटक दिया और मौका आने पर पकड़ लिया। उनकी इसी होशियारी ने दो बार से बंगाल की सत्ता पर उन्हें काबिज होने का मौका दिया। अब वह तीसरी बार बंगाल का किला अपने नाम करने का उपक्रम कर रही हैं।

ममता ने माकपा से लड़ने के लिए 2008 में उसी कांग्रेस से समझौता किया जिसे छोड़कर वह आई थीं। कांग्रेस के साथ समझौते के बाद उन्हें नई ताकत मिली थी। तृणमूल से सांसद बनने के बाद भी वह समझौते की राजनीति कर केंद्र की सरकार में भी शामिल हुईं। बतौर रेल मंत्री उनका कार्यकाल याद किया जाता है। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई चर्चित फैसले लिए। ममता ने भाजपा से हाथ मिलाया और तब वामपंथियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर राजनीति के बदलते परिदृश्य का अनोखा खेल बंगाल में देखने को मिला। जिस कांग्रेस के साथ मिलकर ममता ने वामपंथ के किले में सेंध लगाई अब वही वामपंथी और कांग्रेसी एक साथ हो गए हैं। कांग्रेस-वामो की साझा आवाज ममता सरकार के खिलाफ गूंज रही है और दोनों ममता के लिए चुनौती भी बन रहे हैं। ममता एक तरफ कांग्रेस-वामो के निशाने पर हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में भाजपा के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए विपक्षी एका का भी नारा दे रही हैं। भाजपा ने इस दफा लोकसभा चुनाव में ममता की जमीन खिसका दी और बंगाल की 18 सीटों पर कब्जा जमाकर 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। ममता बनर्जी का फिर इम्तिहान होना है। बंगाल के आवाम की कसौटी पर वह कितना खरा उतरेंगी, उसका पूर्वाभ्यास भी इसी वर्ष होने जा रहे निकाय चुनाव में होना है। इसके लिए वह भरसक कोशिश भी करती दिखाई दे रही हैं।

तृणमूल की स्थापना के बाद वामपंथ का किला ध्वस्त करने के लिए ममता ने कभी कांग्रेस की मदद ली थी, लेकिन आज कांग्रेस-वामो मिलकर ममता को चुनौती दे रहे हैं

ममता बनर्जी जानती हैं कि अब राज्य में उनकी मुख्य लड़ाई भाजपा से है। शायद इसीलिए वह उसके खिलाफ काफी मुखर नजर आ रही हैं। राज्य हो या केंद्र जहां कहीं भी उन्हें मौका मिल रहा है, वहां भाजपा का विरोध करने से चूक नहीं रही हैं। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, नागरिकता संशोधन कानून हो या फिर अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का फैसला हो अगर किसी ने केंद्र पर सबसे तीखा हमला बोला है तो वह ममता बनर्जी ही रही हैं। अब देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका कितना फायदा मिलता है। उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा उसके नतीजों के बाद ही तय होगी।

डाटागीरी

18 साल से कम के 30 लाख लोग करते हैं अल्कोहल का प्रयोग

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

देश में 10 से 17 वर्ष की आयु के 30 लाख लोग अल्कोहल लेते हैं। यह जानकारी बीते दिनों संसद में सामाजिक न्द्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय ने संसद में दी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस आयुवर्ग में अल्कोहल लेने वालों की संख्या में इजाफा 1.3 फीसद की दर से हुआ है। वहीं, इसी आयुवर्ग के 20 लाख लोग भांग का प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 0.9 फीसद की दर से इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस आयुवर्ग के 40 लाख लोग अफीम का इस्तेमाल करते हैं और इनमें वृद्धि की दर 1.8 फीसद है। सीडेटिव (शामक औषध) और इन्हेलेंट लेने वालों की संख्या क्रमशः 20 लाख और 30 लाख है। इसे लेने वालों की संख्या में इजाफे की बात की जाए तो सीडेटिव का प्रयोग करने वालों में 0.58 फीसद और इन्हेलेंट का प्रयोग करने वालों में 1.17 फीसद की दर से वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चार लाख से अधिक लोग एम्फैटेमिन प्रकार के नशीले पदार्थ (एटीएस) का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग करने वालों की संख्या में 0.18 फीसद की दर से वृद्धि देखी गई है। इसके बाद कोकीन और हल्लुसिनोंगे का प्रयोग करने वालों का नंबर आता है। 10 से 17 साल की आयु में इसका प्रयोग करने वालों की संख्या दो-दो लाख है और इनमें वृद्धि क्रमशः 0.06 फीसद और 0.07 फीसद की दर से दर्ज की गई है।

5.1 करोड़ वयस्क अल्कोहल का करते हैं प्रयोग: इस रिपोर्ट में 18 से 75 आयु वर्ग के लोगों के आंकड़ों के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 15.1 करोड़ वयस्क अल्कोहल का प्रयोग करते हैं और इनमें 17.10 फीसद की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, 2.9 करोड़ वयस्क भांग का इस्तेमाल करते हैं और इनमें 3.30 फीसद की दर से वृद्धि देखी गई है। अफीम की बात की जाए तो 1.9 करोड़ वयस्क इसे लेते हैं और इनमें वृद्धि 2.1 फीसद की दर से देखी गई है। सीडेटिव का प्रयोग 1.1 करोड़ लोग और इन्हेलेंट का 60 लाख करते हैं। इनमें वृद्धि क्रमशः 1.21 फीसद और 0.58 फीसद की दर से देखी गई है। इसके अलावा एटीएस का प्रयोग 20 लाख वयस्क करते हैं और इनमें वृद्धि की दर 0.18 फीसद रही, जबकि हल्लुसिनोंगे और कोकीन का इस्तेमाल करने वालों में क्रमशः 0.13 फीसद और 0.11 फीसद की दर से वृद्धि देखी गई।

ये आंकड़े 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण के द्वारा एकत्र किए गए हैं। मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी बताया था कि नशीले पदार्थों के प्रयोग में कमी लाने के लिए 2018-25 के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (एनएपीडीडीआर) तैयार किया गया है और इसे लागू किया जा रहा है।

दो राज्यों में पाबंदी

बता दें कि गुजरात और बिहार में शराब बेचने पर पाबंदी है। वहीं, 10 ऐसे राज्य हैं जहां की 20 फीसद से ज्यादा आबादी अल्कोहल लेती है। इनमें छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा प्रमुख हैं। बिहार और गुजरात को छोड़ दें तो राजस्थान और मेघालय में शराब पीने वाले लोग सबसे कम हैं। राजस्थान में 2.1 फीसद और मेघालय में 3.4 फीसद लोग शराब पीते हैं। वहीं, त्रिपुरा की 62 फीसद आबादी अल्कोहल का प्रयोग करती है। छत्तीसगढ़ में 57.2 प्रतिशत और पंजाब में 51.70 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं।

10-17 आयु वर्ग के बच्चे और किशोर			18-75 आयु वर्ग के वयस्क	
नशे का प्रकार	वृद्धि	संख्या	वृद्धि	संख्या
अल्कोहल	1.30	30 लाख	17.10	15.10 करोड़
भांग	0.90	20 लाख	3.30	2.90 करोड़
अफीम	1.80	40 लाख	2.10	1.90 करोड़
सीडेटिव	0.58	20 लाख	1.21	1.10 करोड़
इन्हेलेंट	1.17	30 लाख	0.58	60 लाख
कोकीन	0.06	दो लाख	0.11	10 लाख
एटीएस	0.18	चार लाख	0.18	20 लाख
हल्लुसिनोंगे	0.07	दो लाख	0.13	20 लाख

सेबों की मिठास को गाढ़ा कर देती है चिल्ले कलां की बर्फ

कश्मीर में अच्छी बर्फबारी से बागवानों को अगले सीजन में सेब की अच्छी पैदावार की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

अपने बाग में चक्कर लगा रहा ताहिर अब्बास बार-बार जमीन की नमी का जायजा ले रहा है। साथ ही वह पास खड़े अपने साथी को पेड़ों की छंटाई का काम जल्द पूरा करने के लिए कह रहा है। अपने साथी से वह कहता है, लाला दुआ करो कि पेड़ न टूटे, इस बार न सिर्फ पैदावार अच्छी होगी, सेब पहले से ज्यादा रसीला और मजबूत होगा। सेंटरोज भी खूब रसीला होगा। हालात ठीक रहे तो हम पूरी तरह फायदे में रहेंगे। वर्तमान में कश्मीर में चिल्ले कलां (सबसे ठंडे 40 दिन) के दौरान अच्छी बर्फबारी हो रही है।

कश्मीर में सालाना 20 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा होता है। करीब सात लाख परिवार सेब उत्पादन और इसके कारोबार से जुड़े हैं। कश्मीर घाटी का शायद ही कोई हिस्सा होगा, जहां सेब पैदा न होता हो। उत्तरी कश्मीर में जिला बारामुला के अंतर्गत सोपोर और दक्षिण कश्मीर में शोपियां व कुलगाम सेब उत्पादन में वादी के अन्य जिलों में अग्रणी हैं।

श्रीनगर-पुलवामा-शोपियां मार्ग पर स्थित छत्तरगाम में रहने वाले ताहिर का सेब और आलू बुखारा जिसे स्थानीय भाषा में सेंटरोज कहते हैं, का बाग है। ताहिर ने कहा कि इस बार नवंबर-दिसंबर में बर्फ खूब गिरी है। जनवरी में भी हिमपात की उम्मीद है। यह बर्फ हम किसानों और बागवानों के लिए नेमत है। यही बर्फ ज्यादा देर तक पहाड़ों पर जमी रहेगी, जिससे गर्मियों में नदी-नालों में पर्याप्त पानी होगा। जमीन में जितनी नमी होगी, हमारा फल उतना रसीला होगा।

कश्मीर में बर्फ से लदे सेब के पेड़। जागरण

बर्फबारी और बारिश के कारण चिलिंग आवर्स पूरे होने की उम्मीद है। एक सीजन में 800 से 1600 घंटे चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। सेब की अलग-अलग किस्मों के लिए चिलिंग आवर्स अलग-अलग होते हैं। सेब की रॉयल किस्म के लिए सबसे अधिक चिलिंग आवर्स चाहिए। मौसम ऐसे ही मेहरबान हुआ तो पैदावार अच्छी होगी।

-डॉ. एमएम शर्मा, बागवानी निदेशक

मौसम की मेहरबानी से हिमाचल भी भरेगा जेब

रमेश सिंगटा, शिमला: मौसम की मेहरबानी से सेब इस बार हिमाचल की समृद्धि के रंग भरेगा। इससे प्रदेश के खजाने में बढ़ोतरी होगी। इस बार हुई बर्फबारी से सेब के लिए जरूरी चिलिंग आवर्स पूरे होने के आसार हैं। ऐसा हुआ तो बागवान बाग-बाग हो जाएंगे। हिमाचल में सेब से करीब चार लाख बागवान परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब का करीब चार हजार करोड़ रुपये का अहम योगदान है। चिलिंग आवर्स सेब की गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं। इसका सीधा संबंध बर्फबारी व बारिश से होता है। हिमाचल में पिछले वर्ष दिसंबर में बर्फबारी हुई व बारिश भी अच्छी हुई थी। इससे सेब की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आगे भी मौसम ऐसे ही मेहरबान रहा तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इससे फल की सेटिंग भी उतनी ही बढ़िया हो पाएगी।

क्या हैं चिलिंग आवर्स

बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार सेब की बढ़िया पैदावार के लिए कड़ाके की सर्दी बेहद जरूरी है। दिसंबर से लेकर मार्च तक के चार महीने में औसतन 1200 चिलिंग आवर्स यानी 1200 सर्द घंटे पूरे हों तो सेब के पौधों से पैदावार बेहतर होती है। सेब के पौधे में फल लगने के लिए सात डिग्री सेल्सियस से कम तापमान बेहद जरूरी है। पौधे नवंबर व दिसंबर में सुप्त अवस्था में होते हैं। उन्हें इस अवस्था से बाहर आने के लिए सात डिग्री सेल्सियस का तापमान औसतन 1200 घंटे तक चाहिए। ये 1200 घंटे चार माह में पूरे हो जाने चाहिए। यदि चार माह में 1200 चिलिंग आवर्स पूरे हो जाएं तो सेब के पौधों में फल की सेटिंग बहुत अच्छी होती है। इससे उत्पादन बंपर होता है। जब चिलिंग आवर्स पूरे हो जाएं तो सेब की फ्लावरिंग बेहतर होगी और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। यदि मौसम दगा दे जाए और चिलिंग आवर्स पूरे न हों तो पौधों में कहीं फूल अधिक आ जाते हैं और कहीं कम। इससे फलों की सेटिंग प्रभावित हो जाती है।

बड़ी इंडस्ट्री खा रही बिजली सब्सिडी का दो तिहाई हिस्सा

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- बाजार में टिकने के लिए सब्सिडी की ज्यादा जरूरत छोटी इंडस्ट्री को है
- पंजाब के वित्त विभाग ने कहा, बड़ी इंडस्ट्री से सुविधा वापस लें तो बचेंगे 1100 करोड़

पंजाब का खजाना इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। उसको संकट से निकालने के लिए भी केवल बैठकें ही हो रही हैं, फैसला नहीं लिया जा रहा। वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के आग्रह पर ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने आवास पर बैठक बुलाते हुए सभी विभागों से खर्चे कम करने और आमदनी के स्रोत बढ़ाने के उपाय बताने के लिए कहा। जब वित्त विभाग ने इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई फैसला नहीं लिया।

दो सप्ताह पहले वित्त विभाग ने उद्योगों को दी जा रही बिजली सब्सिडी पर सवाल उठाया और कहा कि सब्सिडी की जरूरत केवल छोटी इंडस्ट्री को है। वहीं, सरकार की ओर से 1500 करोड़ की सालाना सब्सिडी में से दो तिहाई यानी 1140 करोड़ रुपये की सब्सिडी मात्र 8316 यूनिट्स को ही दी जा रही है। सबसे छोटी इंडस्ट्री को 1500 करोड़ रुपये में से मात्र 138 करोड़ ही मिलते हैं, जबकि इनकी गिनती 99444 बनती है। इसी तरह मीडियम दर्जे की इंडस्ट्री को 175 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है, जबकि उनकी गिनती 31499 है। ऐसे में अगर मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों को जोड़ लिया जाए तो सब्सिडी 313 करोड़ रुपये ही बनती है, जबकि गिनती 1,30,943 यूनिट्स बनती है।

वित्त विभाग का मानना है कि बड़ी इंडस्ट्रीज अपने उत्पादन के कारण टिक सकती हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर हिस्सा सोलर, को-जेनेरेशन आदि से भी चलाया हुआ है। वहीं, छोटी इंडस्ट्री पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर ही टिक पाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री को सब्सिडी बंद करने से सरकार के लगभग 1100 करोड़ रुपये बचेंगे। बताया जाता है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के सुझाव पर कोई फैसला नहीं लिया। उधर, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि न दिए जाने से वित्त विभाग अपने खर्चे में कटौती करने के बारे में सोच रहा है।

कैप्टन सरकार ने सत्ता में आने से पहले इंडस्ट्री को पांच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का वादा किया था। इस फैसले को लागू करने से सरकार पर सालाना 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। एक विभागीय अधिकारी का कहना है कि इसका लाभ केवल बड़ी इंडस्ट्री को ही मिल रहा है, जबकि सरकार को सहायता केवल छोटे और मध्यम दर्जे की इंडस्ट्री को करनी चाहिए।

उत्तराखंड के नेशनल पार्कों में ड्रोन से फोटो व वीडियोग्राफी का रास्ता खुला

केदार दत्त, देहरादून : छह नेशनल पार्क, सात अभयारण्य और चार कंजर्वेशन रिजर्व वाले उत्तराखंड में अब ड्रोन की नजर से कुदरती नजारों व वन्यजीवन का दीदार हो सकेगा। वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर इन क्षेत्रों में नैनो ड्रोन (250 ग्राम से कम वजनी) से फोटो व वीडियोग्राफी के लिए वन विभाग सशर्त अनुमति जारी करेगा। विभाग ने इसके लिए दरों के निर्धारण को शासन से आग्रह किया है। हालांकि, सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग की इजाजत किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। जैव विविधता के मामले में धनी उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन को हर साल चार से पांच लाख सैलानी यहां पहुंचते हैं। इनमें भी पर्यटकों की पहली पसंद विश्व प्रसिद्ध कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क हैं। इसे देखते हुए महकमे ने अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन से फोटो व वीडियोग्राफी के रोमांच का तड़का डालने की पहल की है। उत्तराखंड फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स के समन्वयक डॉ. पराग मधुकर धकाते बताते हैं कि ड्रोन से एरियल फोटो-वीडियोग्राफी से आकर्षण बढ़ेगा और पर्यटक अन्य क्षेत्रों का रुख भी करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम अवसरों पर ड्रोन से फोटो-वीडियोग्राफी का चलन बढ़ा है। ऐसे में डीजीसीए की गाइडलाइन के अनुरूप विभाग ने वन्यजीव पर्यटन में नैनो ड्रोन की सशर्त अनुमति देने का निश्चय किया है। शासन से दरों का निर्धारण होने के बाद ही कदम बढाए जाएंगे।

तृणमूल ने 'नागरिक दिवस' के रूप में मनाया 22वां स्थापना दिवस

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं का जताया आभार
- कहा, लोगों के हित में हमारी लड़ाई है जो जारी रहेगी

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआइटीएमसी) ने बुधवार को अपना 22वां स्थापना दिवस 'नागरिक दिवस' के रूप में मनाया। सुबह ट्वीट करते हुए पार्टी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आज राज्य भर में बूथ स्तर पर 'नागरिक दिवस' मनाया जाएगा क्योंकि हम सभी नागरिक हैं। बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आज तृणमूल ने 22 वर्ष पूरा कर लिया। पार्टी की ओर से मां, माटी (मिट्टी), मानुष (मनुष्य) को श्रद्धेय प्रणाम। जो सभी कार्यकर्ता-समर्थक निःस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करते हैं उनका अभिनंदन। लोगों के आर्शीवाद के बगैर आज तृणमूल इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। आज राज्य भर में बूथ स्तर पर 'नागरिक दिवस' मनाया जाएगा। हम सभी नागरिक हैं। लोगों के हित में हमारी लड़ाई है जो जारी रहेगी। जय हिंद, जय बांग्ला।'

उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह ही ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस को 'नागरिक दिवस' के रूप में मनाने का निर्देश दिया था। वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कोलकाता में 11 दिनों के अंदर पांच बार सड़क पर उतर कानून का विरोध जता चुकी हैं और अब वह जिलों में भी कानून के खिलाफ पैदल मार्च निकाल रही हैं।

ममता बनर्जी फाइल

पार्टी की ओर से भी विधानसभा स्तर पर उक्त मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन जारी है। माना जा रहा है कि स्थापना दिवस के दिन सीएए-एनआरसी के खिलाफ संदेश देकर तृणमूल सुप्रीमो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव और 2021 विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाएगी। इससे पहले बीते साल इसी मुद्दे पर उपचुनाव लड़ी तृणमूल को तीनों ही सीटों पर जीत मिली थी। बताते चलें कि 1 जनवरी 1998 को स्थापित तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान में लोकसभा में 22 जबकि राज्यसभा में 13 सीटें हैं।